(d) No, Sir.

(e) Consultation with the Ministry of Water Resources was not necessary.

(f) The height of the lowest block of the Sardar Sarovar Dam has been raised upto Elevation Level 69 metres. The progress in regard to the construction of Narmada Main Canal and its distributaries till the end of January, 1994 is as under :

(Percentage)

	Earthwork	Lining	Structural concrete
Phase-I (00 to 82 Km.)	86.88	59.95	74.95
(82 to 144.5 Km.)	85.59	68.18	32.97
Branch Canals			
Phase-I (0 to 144.5 Km.)	59.24	30.85	44.07

(g) The Unit-wise expenditure incurred upto the end of February, 1994 on Sardar Sarovar Project is as under :

Unit	Component	Amount (Rs. in crores)
I	Dam & appurtenant works	124.47
II-A	Main Canal	611.91
II-B	Branches & distribution systems	2224.12
III	Power	590.77

(h) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

विद्युत परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियां

5201. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नर्मदा परियोजना को ''राष्ट्रीय योजना'' के रूप में घोषित करने का विचार रखती है;

(ख) क्या महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों की सरकारों ने चार बड़ी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की मांग की है;

(ग) 1987-88 के मूल्यों के आधार पर इन चार परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या होगी और मूल्य वृद्धि के बाद नवीं पंच-वर्षीय योजना में इनकी अनुमानित लागत क्या होगी; और

(घ) नर्मदा जल विवाद अधिनिर्णय के अनुसार इन राज्यों को नर्मदा का कितना जल आवंटित किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) यद्यपि नर्मदा परियोजनाएं राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं हैं, फिर भी किसी भी परियोजना को ''राष्ट्रीय परियोजना'' के रूप में घोषित नहीं किया गया है।

(ख) जापान सरकार से ओवरसीज इकोनामिक को-ऑपरेशन फंड ऋण सहायता के बंद हो जाने के कारण तथा वित्त पोषण की वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने के लिए सरदार सरोवर परियोजना के नदी तल विद्युत घर के वास्ते टरबो-जनरेटिंग सेट खरीदने हेतु विद्युत क्षेत्र घटक हेतु महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सरकारों ने अतिरिक्त निधियां मांगी हैं। नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर तथा महेश्वर नामक अन्य तीन परियोजनाओं को मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। नर्मदा सागर परियोजना को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मांगी है।

(ग) नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर, नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर और महेश्वर परि-

योजनाओं की 1987 के मूल्य स्तर पर अनुमानित लागत निम्न प्रकार है :

करोड़ रुपए

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत
सरदार सरोवर परियोजना	6406.04
नर्मदा सागर परियोजना	1993.67
ओंकारेश्वर	1616.04
महेश्वर	465.63

(घ) नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार 75% विश्वसनीयता पर 28 मिलियन एकड़ के रूप में आंकी गई नर्मदा जल उपयोज्य मात्रा भागीदार राज्यों में निम्न प्रकार आबंटित की जाएगी :

मिलियन एकड़ फुट

मध्य प्रदेश	18.25
गुजरात	9.00
महाराष्ट्र	0.25
राजस्थान.	0.50
कुल :	28.00

Appointment of Commission for Reservation for OBCs

5202. SHRI CHIMANBHAI MEHTA :
SHRI MOHD. MASUD KHAN:
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY :
SHRI SARADA MOHANTY :
SHRI SHANKAR DAYAL SINGH :

Will the Minister of WELFARE be pleased to state whether there is any proposal under Government's consideration to appoint a commission to assess the benefits of reservation to upper stratum of OBC ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU) : No, Sir.

Scheme for the welfare of Scheduled Castes in U.P.

5203. DR. MURLI MANOHAR JOSHI :
SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI :

Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of U.P. have submitted a number of schemes in 1993 for the welfare of Scheduled Castes ;

(b) if so, the salient features of each of the scheme and the reasons for the delay in clearing them ; and

(c) whether Government have made any budget allocation for any of the above schemes in 1994, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU) : (a) to (c) In 1993, Uttar Pradesh Government submitted schemes for the welfare of Scheduled Castes which were sanctioned by the Ministry of Welfare and an additional amount of Rs. 9.70 crores as Special Central Assistance was given therefor. The schemes are given in the enclosed statement-I (*See* below) .

Besides, the Planning Commission approved the following schemes of the Uttar Pradesh Government :

(i) Mess charges to girl students;

(ii) Compulsory scholarship to girl students studying in Primary level classes.

During 1993-94, Uttar Pradesh was sanctioned the amounts as detailed in Annexure-II as Central assistance for the ongoing Central/Centrally Sponsored Schemes for the welfare of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes. All the Central/Centrally Sponsored schemes have been provided budget allocation in 1994-95 as given in the enclosed statement-II.